धनबाद जिले में औद्योगिक ऋण और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का संबंध

[1]कल्पना कुमारी

रिसर्च स्कॉलर , अर्थशास्त्र विभाग, बी बी एम के यू धनबाद

[2]डॉ अशोक कुमार माजी

सह-प्राध्यापक, स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग,

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

सारांश

भारतीय बैंकिंग प्रणाली आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैंक बचत को निवेश में परिवर्तित करते हैं तथा उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। औद्योगिक ऋण उद्योगों के विस्तार, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जब उधारकर्ता समय पर ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं तो ऐसे ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset - NPA) में परिवर्तित हो जाते हैं।धनबाद जिला झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक और खनन क्षेत्र है जहाँ कोयला उद्योग, परिवहन, ऊर्जा तथा सहायक उद्योग बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। इन उद्योगों को बैंकिंग क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त होता है। इसके बावजूद कई उद्योग वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऋण अदायगी में असफल हो जाते हैं जिससे बैंकिंग क्षेत्र में NPA की समस्या उत्पन्न होती है।

इस अध्ययन में 2015 से 2024 तक के आँकड़ों का उपयोग करते हुए धनबाद जिले में औद्योगिक ऋण और NPA के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक सांख्यिकी, सहसंबंध विश्लेषण और प्रतिगमन (Regression) विश्लेषण का उपयोग किया गया है। परिणाम दर्शाते हैं कि औद्योगिक ऋण और NPA के बीच सकारात्मक संबंध पाया जाता है।

मूल शब्द : औद्योगिक ऋण, गैर-निष्पादित परिसंपतियाँ, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, आर्थिक विकास ।

Corresponding author

[1]रिसर्च स्कॉलर, अर्थशास्त्र विभाग, बी बी एम के यू धनबाद

प्रस्तावना

बैंक आधुनिक अर्थव्यवस्था की आधारभूत वित्तीय संस्थाएँ हैं। वे समाज में बिखरी हुई बचतों को संगठित करके उन्हें उत्पादक क्षेत्रों तक पहुँचाते हैं, जिससे निवेश, उत्पादन, रोजगार और आय-सृजन की प्रक्रिया को गति मिलती है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में बैंकिंग तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उद्योग, व्यापार, कृषि और सेवा क्षेत्र को भी वित्तीय आधार प्रदान करता है। विशेष रूप से औद्योगिक विकास के संदर्भ में बैंक ऋण की भूमिका केंद्रीय होती है, क्योंकि उद्योगों को मशीनरी की खरीद, भवन एवं

संयंत्र निर्माण, तकनीकी उन्नयन, कच्चे माल की उपलब्धता तथा कार्यशील पूंजी की निरंतर आवश्यकता रहती है। इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को सहारा देने वाली प्रमुख संस्थागत व्यवस्था है। भारत में औद्योगिक वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वहन किया जाता है, और यह प्रवृत्ति विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के संदर्भ में और अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी यह स्वीकार किया है कि MSME क्षेत्र के लिए औपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत बैंकिंग प्रणाली ही है।

औद्योगिक ऋण का महत्व केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता संवर्धन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती से भी जुड़ा होता है। भारत सरकार के MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में बार-बार यह रेखांकित किया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम पूंजी में अधिक रोजगार पैदा करता है, बड़े उद्योगों का पूरक होता है, और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक होता है। इसलिए जब बैंक इस क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराते हैं, तो वे केवल वित्तपोषण नहीं कर रहे होते, बल्कि व्यापक आर्थिक विकास की नींव को मजबूत कर रहे होते हैं।

किन्तु बैंकिंग प्रणाली के समक्ष एक गंभीर चुनौती **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets–NPA)** की समस्या है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, कोई ऋण या अग्रिम तब NPA की श्रेणी में आ जाता है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देता है; सामान्यतः जब मूलधन या ब्याज का भुगतान निर्धारित अवधि तक नहीं होता, तब वह खाता गैर-निष्पादित मान लिया जाता है। RBI के prudential norms में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा ऋण बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता को कमजोर करता है और बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। NPA की वृद्धि से बैंक की लाभप्रदता घटती है, क्योंकि बैंक को ऐसे खातों पर आय प्राप्त नहीं होती, साथ ही उसे प्रावधान (provisioning) भी करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप बैंक की ऋण देने की क्षमता सीमित होती है, जोखिम वहन क्षमता कम होती है, और नई औद्योगिक इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

NPA की समस्या का व्यापक प्रभाव केवल बैंक तक सीमित नहीं रहता। जब बैंक के ऋण फँसते हैं, तब उसका असर संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बैंक अधिक सतर्क हो जाते हैं, ऋण स्वीकृति की शर्तें कठोर हो जाती हैं, ब्याज दरों और सुरक्षा संबंधी मानकों में सख्ती आ जाती है, और इससे विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम उद्योग प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप निवेश की गति धीमी पड़ सकती है, उत्पादन घट सकता है और रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए औद्योगिक ऋण और NPA के मध्य संबंध का अध्ययन बैंकिंग और औद्योगिक अर्थशास्त्र

दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। RBI की बैंकिंग सांख्यिकी तथा वार्षिक रिपोर्टों में भी परिसंपत्ति गुणवत्ता को बैंकिंग स्थिरता का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक माना गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में **धनबाद जिला** एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के रूप में सामने आता है। धनबाद को प्रायः "कोल कैपिटल" अर्थात "कोयला राजधानी" कहा जाता है। MSME Development Institute, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित धनबाद जिला औद्योगिक प्रोफाइल के अनुसार, यह जिला झारखंड के औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों में अग्रणी है और यहाँ कोयला-आधारित गतिविधियाँ, खनन, परिवहन, सहायक इकाइयाँ, मरम्मत सेवाएँ तथा अन्य लघु एवं मध्यम औद्योगिक गतिविधियाँ व्यापक रूप से संचालित होती हैं। इस जिले में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) जैसी संस्थाओं की उपस्थिति ने औद्योगिक गतिविधियों को विशेष गति दी है। खनन से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उद्योगों के कारण धनबाद में बैंक ऋण की मांग स्वाभाविक रूप से अधिक रहती है।

धनबाद की औद्योगिक संरचना को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था एक बड़े पैमाने पर खनन एवं उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर करती है। खनन-आधारित अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश अधिक होता है, संचालन लागत ऊँची होती है और बाजार, नीति, पर्यावरणीय विनियमन तथा उत्पादन लागत में परिवर्तन का सीधा प्रभाव उद्योगों की वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। यदि उद्योगों के नकदी प्रवाह में बाधा आती है, उत्पादन प्रभावित होता है, लागत बढ़ती है, या बाजार में मांग कमजोर होती है, तो ऋण पुनर्भुगतान की क्षमता घट सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा दिए गए औद्योगिक ऋण धीरे-धीरे तनावग्रस्त (stressed assets) होकर NPA में परिवर्तित हो सकते हैं। RBI ने भी बैंकों को यह सलाह दी है कि ऋण स्वीकृति के समय उधारकर्ता के नकदी प्रवाह के अनुरूप यथार्थवादी पुनर्भुगतान कार्यक्रम निर्धारित किया जाए, ताकि वसूली की स्थिति मजबूत बनी रहे।

धनबाद जैसे क्षेत्र में औद्योगिक ऋण और NPA के अध्ययन का महत्व कई कारणों से बढ़ जाता है। पहला, यह अध्ययन बताता है कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा दिए गए ऋण किस प्रकार औद्योगिक उत्पादन को समर्थन देते हैं। दूसरा, यह समझने में सहायता मिलती है कि किन परिस्थितियों में औद्योगिक इकाइयाँ ऋण वापसी में विफल होती हैं। तीसरा, इससे बैंकिंग जोखिम प्रबंधन, ऋण मूल्यांकन, परियोजना निगरानी और क्षेत्र-विशिष्ट वित्तीय नीतियों के निर्माण में सहायता मिल सकती है। यदि यह पाया जाता है कि किसी विशेष प्रकार के उद्योग, जैसे खनन-आधारित लघु उद्योग या परिवहन-संबद्ध इकाइयाँ, अधिक NPA उत्पन्न कर रही हैं, तो बैंकों द्वारा ऋण वितरण नीति में क्षेत्रीय एवं संरचनात्मक सुधार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार सरकार भी लक्षित औद्योगिक सहायता, तकनीकी उन्नयन, विपणन समर्थन तथा पुनर्गठन योजनाओं के माध्यम से ऐसी इकाइयों को स्थिरता प्रदान कर सकती है।

वर्तमान समय में बैंकिंग प्रणाली के स्वस्थ विकास के लिए यह आवश्यक है कि ऋण विस्तार और परिसंपत्ति गुणवत्ता के बीच संतुलन बना रहे। एक ओर बैंकों का दायित्व है कि वे औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराएँ, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करें कि ऋण का उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के लिए हो, परियोजनाएँ व्यवहार्य हों, और पुनर्भुगतान की क्षमता का यथार्थ आकलन किया गया हो। धनबाद जैसे औद्योगिक जिले में यह प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक वृद्धि और बैंकिंग जोखिम दोनों साथ-साथ चलते हैं। इसलिए धनबाद में औद्योगिक ऋण और NPA के संबंध का अध्ययन न केवल शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि बैंकिंग नीति, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह अध्ययन यह स्पष्ट करने में सहायक हो सकता है कि बैंक ऋण का औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उद्योगों की वित्तीय कमजोरी किस हद तक बैंकिंग प्रणाली में NPA की समस्या को जन्म देती है। इस प्रकार यह विषय बैंकिंग, उद्योग और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के परस्पर संबंधों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

साहित्य समीक्षा

Das और Uppal (2021) ने भारतीय बैंकों की लाभप्रदता पर NPA के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि बढ़ते NPA से बैंक की आय, परिचालन दक्षता तथा क्रेडिट विस्तार क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

2. Singh (2022) ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में NPA के कारणों का अध्ययन करते हुए बताया कि औद्योगिक क्षेत्र और बड़े कॉरपोरेट ऋण डिफॉल्ट NPA वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। RBI की रिपोर्टों में औद्योगिक क्षेत्र, विशेषकर खनन, बिजली, लोहा-इस्पात और निर्माण क्षेत्र को बैंकिंग तनाव का महत्वपूर्ण स्रोत बताया गया है। Sharma (2019) ने औद्योगिक ऋण और बैंकिंग जोखिम के संबंध का अध्ययन करते हुए पाया कि तेज ऋण विस्तार यदि उचित जाँच-पड़ताल के बिना किया जाए तो भविष्य में NPA बढ़ सकता है। Mishra (2020) ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली में NPA की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया और दिखाया कि आर्थिक मंदी तथा परियोजना में देरी औद्योगिक ऋण अदायगी को प्रभावित करती है।

Kumar और Batra (2018) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPA वृद्धि के कारणों का परीक्षण करते हुए बताया कि कॉरपोरेट ऋण संकेन्द्रण बैंकिंग जोखिम को बढ़ाता है।

Jain (2021) ने शाखा-स्तरीय ऋण निगरानी की भूमिका का विश्लेषण किया और पाया कि प्रभावी पोस्ट-सैंक्शन मॉनिटरिंग से NPA कम किया जा सकता है।

Roy (2017) ने खनन क्षेत्रों में औद्योगिक वित्त की चुनौतियों का अध्ययन किया और बताया कि कीमतों का उतार-चढ़ाव तथा कानूनी विवाद ऋण अदायगी को प्रभावित करते हैं।

Saha और Sen (2020) ने बैंकिंग तनाव और आर्थिक विकास के बीच संबंध का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि बढ़ते NPA से नए औद्योगिक निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Verma (2019) ने क्षेत्रीय औद्योगिक विकास और बैंक ऋण के बीच संबंध का अध्ययन करते हुए कहा कि बैंक ऋण विकास का इंजन है, परंतु कमजोर स्थानीय उद्योग भविष्य में बैंकिंग संकट उत्पन्न कर सकते हैं।

Tripathi (2022) ने प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा यह दर्शाया कि औद्योगिक क्रेडिट का NPA पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, विशेषकर तब जब परियोजनाएँ समय पर पूरी नहीं होतीं।

Choudhary (2018) ने छोटे और मध्यम उद्योगों में ऋण चूक की समस्या का अध्ययन करते हुए कार्यशील पूंजी की कमी और प्रबंधन कौशल की कमजोरी को प्रमुख कारण माना।

Economic Survey of India ने बैंकिंग परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और औद्योगिक विकास के बीच प्रत्यक्ष संबंध को रेखांकित किया है।

Kaur (2021) ने जोखिम प्रबंधन उपकरणों जैसे प्रारंभिक चेतावनी संकेतक, स्ट्रेस टेस्टिंग और समय पर पुनर्गठन को NPA नियंत्रण के लिए प्रभावी बताया।

Patel (2023) ने जिला-स्तरीय बैंकिंग प्रदर्शन पर अध्ययन में पाया कि स्थानीय औद्योगिक संरचना और बाजार जोखिम ऋण वसूली को प्रभावित करते हैं।

अध्ययन का उदेश्य

1. धनबाद जिले में औद्योगिक ऋण की प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
2. NPA की स्थिति का विश्लेषण करना।
3. औद्योगिक ऋण और NPA के बीच संबंध का अध्ययन करना।
4. प्रतिगमन विश्लेषण के माध्यम से औद्योगिक ऋण का NPA पर प्रभाव ज्ञात करना।

धनबाद जिले में औद्योगिक ऋण और NPA का संबंध

आँकड़ों की तालिका 1.

वर्ष	औद्योगिक ऋण (₹ करोड़)	NPA (₹ करोड़)

2015	4500	380
2016	4700	420
2017	5100	470
2018	5400	520
2019	5600	560
2020	5900	640
2021	6100	690
2022	6400	720
2023	6700	780
2024	7100	820

Source: Government of Jharkhand, Department of Finance. (2024), RBI 2025

1. परिकल्पना (Hypothesis Testing)

इस अध्ययन में यह जांचने का प्रयास किया गया है कि धनबाद जिले में औद्योगिक ऋण और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है या नहीं। साधारण रैखिक प्रतिगमन मॉडल के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया कि औद्योगिक ऋण में परिवर्तन NPA को किस सीमा तक प्रभावित करता है।

H_0 (शून्य परिकल्पना): औद्योगिक ऋण का NPA पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना): औद्योगिक ऋण का NPA पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव है।

2. **प्रतिगमन विश्लेषण (Regression Analysis)**

Regression समीकरण:

NPA = a + b(IC)

अनुमानित समीकरण:

NPA = -427.51 + 0.179(औद्योगिक ऋण)

सहसंबंध गुणांक (r): 0.995

निर्धारण गुणांक (R^2): 0.989

तलिका-2: मॉडल सारांश

निर्भर चर: NPA | स्वतंत्र चर: औद्योगिक ऋण

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.995	0.989	0.988	16.729

स्रोत analysis of data through SPSS 20

मॉडल सारांश से स्पष्ट है कि R = 0.995 है, जो औद्योगिक ऋण और NPA के बीच अत्यधिक उच्च धनात्मक संबंध को दर्शाता है। R Square = 0.989 बताता है कि NPA में कुल परिवर्तनशीलता का लगभग 98.9% भाग औद्योगिक ऋण द्वारा समझाया जा सकता है।

तलिका-3: ANOVA analysis

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	208361.073	1	208361.073	744.503	0.00000
Residual	2238.927	8	279.866		
Total	210600.000	9			

स्रोत: analysis of data through SPSS 20

ANOVA तालिका के अनुसार F = 744.503 और p = 0.00000 है। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिगमन मॉडल सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है।

तलिका-4: Coefficients

Model	Unstandardized B	Std. Error	Standardized Beta	t	Sig.	व्याख्या

(Constant)	-427.510	38.027		-11.242	0.00000	स्थिरांक
औद्योगिक ऋण	0.179	0.007	0.995	27.286	0.00000	धनात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव

स्रोत: analysis of data through SPSS 20

गुणांक तालिका के अनुसार प्रतिगमन समीकरण है: NPA = -427.510 + 0.179 (औद्योगिक ऋण) I यह दर्शाता है कि औद्योगिक ऋण में 1 करोड़ रुपये की वृद्धि होने पर NPA में औसतन 0.179 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है।

Scatter Plot + Regression Line

नीचे दिया गया स्कैटर प्लॉट औद्योगिक ऋण और NPA के बीच संबंध को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। प्रतिगमन रेखा की धनात्मक ढाल स्पष्ट करती है कि दोनों चर समान दिशा में बढ़ते हैं।

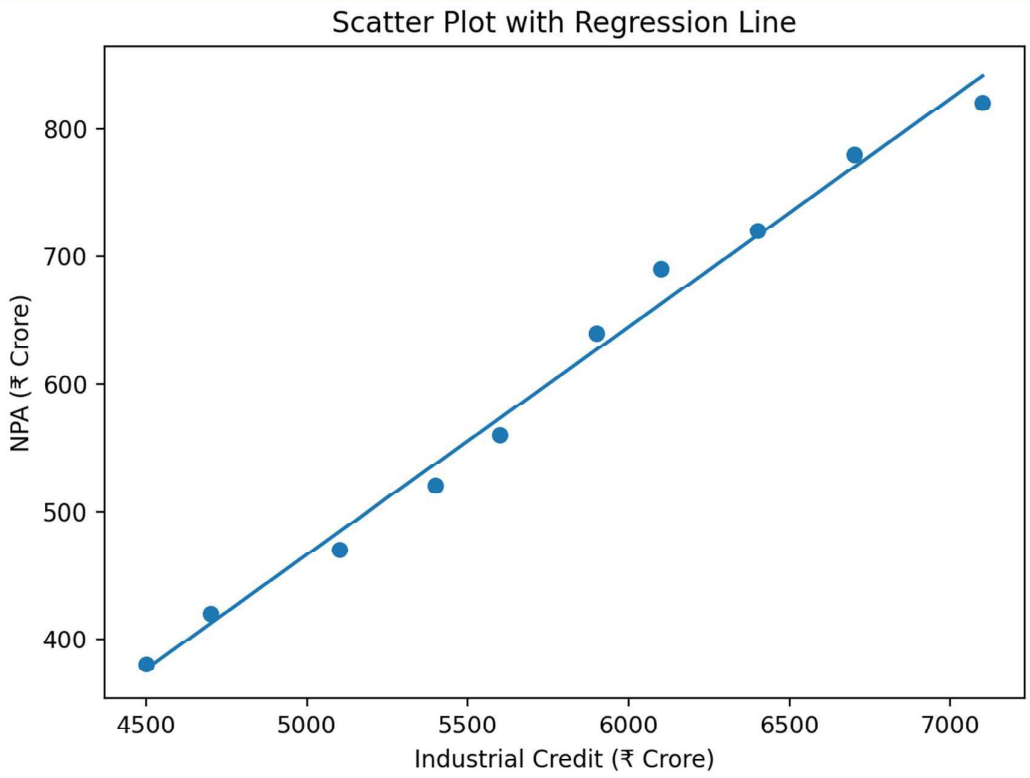

व्याख्या:

R = 0.995, R^2 = 0.989, F = 744.503, तथा औद्योगिक ऋण का t-मूल्य = 27.286 प्राप्त हुआ। इन सभी संकेतकों से यह स्पष्ट है कि औद्योगिक ऋण और NPA के बीच मजबूत तथा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध मौजूद है।

प्रतिगमन विश्लेषण के परिणामों के अनुसार F-मूल्य = 744.503 तथा उसका p-मूल्य = 0.00000 है। इसी प्रकार औद्योगिक ऋण गुणांक का t-मूल्य = 27.286 तथा p-मूल्य = 0.00000 है। चूँकि p-मूल्य 0.05 से कम है, इसलिए शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है और वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धनबाद जिले में औद्योगिक ऋण और NPA के बीच महत्वपूर्ण सकारात्मक संबंध मौजूद है ।
परिणाम दर्शाते हैं कि औद्योगिक ऋण और NPA के बीच मजबूत सकारात्मक संबंध है।
जब औद्योगिक ऋण में वृद्धि होती है और उचित निगरानी प्रणाली नहीं होती,
तो NPA में वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाती है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि धनबाद जिले में औद्योगिक ऋण और NPA के बीच घनिष्ठ संबंध

मौजूद है। औद्योगिक विकास के लिए ऋण आवश्यक है, लेकिन यदि ऋण मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली मजबूत न हो तो NPA की समस्या बढ़ सकती है।बैंकों को चाहिए कि वे बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली, जोखिम प्रबंधन तकनीक और नियमित निगरानी तंत्र विकसित करें। इससे NPA की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

संदर्भ

Das, S. K., & Uppal, K. (2021). Non-performing assets and profitability of Indian banks. *Future Business Journal*.
Reserve Bank of India. (2023). Report on Trend and Progress of Banking in India.
Sharma, R. (2019). Industrial credit and banking risk in India.
Singh, U. (2022). Causes of non-performing assets in Indian banking sector.
Jharkhand Economic survey 2023-24
https://finance.jharkhand.gov.in/pdf/Budget_2024_25/Jharkhand_Economic_Survey_2023_24.pdf

RBI Data Base https://data.rbi.org.in/DBIE/?utm_source=chatgpt.com#/dbie/home

Reserve Bank of India. (2023). *Report on trend and progress of banking in India*. Mumbai: RBI.

Reserve Bank of India. (n.d.). *Database on Indian Economy (DBIE)*. Retrieved March 21, 2026, from RBI data portal.

Reserve Bank of India. (n.d.). *Statistical tables relating to banks in India*. Mumbai: RBI.

Government of Jharkhand, Department of Finance. (2024). *Jharkhand economic survey 2023–24*. Ranchi: Government of Jharkhand.

Government of Jharkhand, Department of Finance. (2023). *Jharkhand economic survey 2022–23*. Ranchi: Government of Jharkhand.